

हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-

बी-4 घंटी वाला कॉम्प्लेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210 मो. 9879141480

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480

सूरत, वर्ष: 1 अंक: 235, गुरुवार, 20 सितम्बर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.

Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com

www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

हाईकोर्ट ने दिल्ली में अनधिकृत पैथोलॉजी लैब्स के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए

नई दिल्ली, एजेंसी। राजधानी दिल्ली में चल रहे अनधिकृत पैथोलॉजी लैब और क्लीनिकों को एक गंभीर मुद्दा बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को ‘आप’ सरकार को उन कदमों के बारे में बताने निर्देश दिया जो इन्हें नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए जाने तक इनके नियमन के लिए उठाए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वीके राव की बेंच ने दिल्ली सरकार को उन लैबोरेट्री और क्लीनिकों का निरीक्षण करने और यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि कौन उन्हें संचालित कर रहे हैं और किस कानून के तहत उन्हें खोला गया है। कोर्ट ने कहा कि निरीक्षण के बाद सरकार को एक हलफनामा दाखिल कर उन कदमों के बारे में बताना चाहिए, जो इसके लिए एक कानून बनाए जाने तक उनके नियमन के लिए उठाए जा सकते हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दिल्ली में अनधिकृत रूप से चल रही पैथोलॉजी लैबों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए दिल्ली के प्रधान स्वास्थ्य सचिव को निर्देश जारी किए हैं। बेंच ने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है। जब तक एक नया कानून नहीं आता है, इस तरह की गतिविधियों को नियमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। बहरहाल, अदालत ने मामले को आगे सुनवाई 30 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया है।

दिल्ली एयरपोर्ट पर 51.64 लाख की विदेशी मुद्रा की तस्करी में एक व्यक्ति गिरफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हवाईअड्डे पर 51.64 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की कथित रूप से तस्करी की कोशिश कर रहे एक भारतीय को सीमा शुल्क अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है। बुधवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, आरोपी को मंगलवार हवाईअड्डा पर रोका गया। वह बैंकॉक जा रहा था। सीमा शुल्क विभाग ने बयान में कहा कि संदेह होने पर सुरक्षा कर्मियों ने यात्री और उसके सामान की तलाशी ली। उसके पास से 72,900 डॉलर की विदेशी मुद्रा बरामद हुई। उसने यह मुद्रा अवैध तरीके से देश से बाहर तस्करी करने के इरादे से रखी थी। इसके अनुसार यह विदेशी मुद्रा 51.64 लाख रुपये के बराबर है, जिसे जब्त कर लिया गया है और यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है।

3 पुलिस वालों पर FIR दर्ज होने के बाद काम पर लौटे वकील

ग्रेटर नोएडा। पुलिसकर्मों द्वारा वकील को थपड़ मारने के विरोध में जारी हड़ताल बुधवार को खत्म हो गई। जनपद दीवानी एवं फ़ैजदारी बार एसोसिएशन गौतमबुद्ध नगर ने 3 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद हड़ताल वापस ले ली है। वकीलों की मांग पर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के मालिक के साथ ही तीन पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद कोर्ट का कामकाज शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक, एक वकील के साथ हुए विवाद में फंस-3 चौकी में एक सिपाही ने थपड़ मार दिया था। इससे गुस्साए वकीलों ने अदालती काम रोक दिया था और कोर्ट में तालाबंदी कर दी थी। दरअसल, कुछ वकील एक हाउसिंग प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे। इसी दौरान एक पुलिसकर्मों ने एक वकील को थपड़ मार दिया था।

हरियाणा: 20 साल की महिला से गैंगरेप, दोस्त को रस्सी से बांधकर जंगल में फेंका

गुडगांव। हरियाणा के रेवाड़ी में हुए गैंगरेप का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि फिर बल्लभगढ़ में एक गैंगरेप की वारदात सामने आई है। यहां मंगलवार रात एक 20 साल की लड़की के साथ मारपीट कर गैंगरेप करने का आरोप है। फरीदाबाद के सेक्टर-3 में रहने वाली 20 साल की एक लड़की मंगलवार रात करीब 10 बजे अपने एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर आईएमटी की तरफ घूमने गई थी। वहां आउटर बाईपास पर चार लोगों ने उनकी बाइक रुकवा ली और दोनों के साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद चारों लोगों ने युवती के दोस्त को रस्सियों से बांधकर जंगल में फेंक दिया और फिर सभी ने युवती के साथ बारी-बारी बलात्कार किया। युवती ने जब इसका विरोध किया तो उन युवकों ने उसके साथ मारपीट की और अपनी हवस का शिकार बनाते रहे। एसीपी बल्लभगढ़ बलवीर सिंह की मानें तो उन्हें मंगलवार रात को सूचना मिली थी।

दैनिक

क्रांति समय

RNI.No.: GUJHIN/2018/75100

हमारे यहां पर एल.आई. सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-

बी-4 घंटी वाला कॉम्प्लेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210 मो. 8980974047

E-mail: krantisamay@gmail.com

रजिस्टर्ड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

केजरीवाल, सिसोदिया व 11 आप विधायकों को समन

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा आप के 11 विधायकों को बतौर आरोपी समन जारी किया है।

पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि आरोप पत्र में पेश

साक्ष्यों के आधार पर सभी के खिलाफ समन जारी करने के पर्याप्त आधार हैं। उन्होंने यह कहते हुए सभी से 25 अक्टूबर को पेश होने को कहा। इस मामले में अदालत ने पुलिस के 13 अगस्त को दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए 11 विधायक अमानतुल्ला खान, प्रकाश जारवाल, नितिन त्यागी, ऋतुराज गोविंद, संजीव झा, अजय दत्त, राजेश ऋषि, राजेश गुप्ता, मदन लाल, प्रवीण

कुमार व दिनेश मोहनिया को भी समन जारी किया है। अदालत ने 25 अगस्त को आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुये आरोपियों को समन जारी करने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अगले सुनवाई के दिन आरोपियों के पेश होने पर उन्हें आरोप पत्र की प्रति दी जाएगी और उनके जमानत याचिका दाखिल किये जाने की दशा में उसपर विचार किया जाएगा। आरोप पत्र में कहा

गया है कि केजरीवाल के सरकारी आवास पर विगत 19 फरवरी की रात की बैठक में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ बदसलुकी की और मारपीट की। गत सुनवाई के दिन अदालत ने केजरीवाल सहित अन्य विधायकों के उस अनुरोध को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने पुलिस से आरोप पत्र के मुद्दे को मीडिया के साथ साझा करने से रोकने का आग्रह किया था।

दिव्यांगों के कार्यक्रम में बोले मंत्री बाबुल सुप्रियो- तोड़ सकते हैं तुम्हारी टांग

एजेंसी ,नई दिल्ही। वैसे तो केन्द्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के लिए विवाद कोई नया नहीं। लेकिन इस बार फिर से वह एक विवाद में उस वक्त आ गए जब उन्होंने लोगों को अपने संबोधन के दौरान एक शख्स के पैर तोड़ने और उसके हाथ में बैसाखी देने की बात कही। केन्द्रीय मंत्री एक वीडियो में पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मंच से यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं।

रॉफेल: कांग्रेस के आरोपों पर रक्षा मंत्री का पलटवार

यूपीए के समय ही डील से बाहर हो गई थी एचएएल

नई दिल्ली ■ एजेंसी

रॉफेल विमान सौदे पर सरकार और प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी द्वारा मंगलवार को लगाए गए आरोपों पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया। रक्षा मंत्री ने रॉफेल डील से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के बाहर होने को लेकर कांग्रेस की यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पिछली सरकार के समय में ही सरकारी कंपनी प्रॉडक्शन टर्मस पर डसॉल्ट एविएशन से सहमत नहीं हो सकी। ऐसे में यूपीए सरकार के समय में ही एचएएल डील से बाहर हो गई थी।

उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए सरकार को राफेल लड़ाकू विमान यूपीए के समय हुई डील से 9 फीसदी सस्ते रेट पर मिल रहे हैं। निर्मला ने कहा, कि डील यूपीए के दौरान नहीं हुई। इसके अलावा यूपीए के दौरान एचएएल और डसॉल्ट के बीच प्रॉडक्शन टर्मस को लेकर सहमति भी नहीं बन सकी थी। ऐसे में एचएएल और रॉफेल एक साथ काम नहीं कर सकते थे। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि एचएएल के साथ कौन नहीं गया, किस सरकार के समय ऐसा हुआ? कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए।

आखिर कितना सस्ता है रॉफेल?

इससे पहले कांग्रेस के नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा था कि मोदी सरकार कह रही है कि राफेल सस्ते रेट पर खरीदे जा रहे हैं तो सरकार ने संख्या कम क्यों कर दी। उन्होंने कहा कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल में दावा किया था कि नए अग्नीमैट में एयरक्रॉफ्ट यूपीए डील की तुलना में 9 पसेंट सस्ता मिल रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह 20 पसेंट सस्ता मिल



किस बात को लेकर है विवाद?

दरअसल, पूरा मामला एचएएल को नजरअंदाज कर रिलायंस को डसॉल्ट से कॉन्ट्रैक्ट मिलने का है। विपक्ष इस पर सरकार को घेरने में लगा है। इससे पहले अनुभव की कमी और सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को नजरअंदाज किए जाने के मुद्दों पर रिलायंस ने जवाब दिया था। कंपनी ने अपनी सफाई में कहा था कि डसॉल्ट ने रिलायंस डिफेंस को ऑफसेट या एक्सपोर्ट काम के लिए चुना है। विदेशी वेंचर के लिए भारतीय पार्टनर चुनने में रक्षा मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है।

रहा है, जबकि एयर फोर्स के एक अधिकारी ने कहा कि यह 40 पसेंट सस्ता है। एंटनी ने कहा कि अगर इतना ही सस्ता है तो 126 से ज्यादा क्यों नहीं खरीदे गए।

जेपीसी से बच रही सरकार: एंटनी

कांग्रेस ने रॉफेल विमान सौदे में 'प्रक्रियाओं का उल्लंघन' करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी ने सवाल किया कि आखिर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से बचकर सरकार क्या छिपाने की कोशिश कर रही है?

दिल्ली हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष विष्णु खरे का निधन, जीबी पंत अस्पताल में ली अंतिम सांस

नई दिल्ली। हिंदी के प्रख्यात कवि, वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार एवं दिल्ली हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष विष्णु खरे का बुधवार को दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में निधन हो गया। बीते 12 सितंबर को ब्रेन हैमरेज के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ब्रेन हैम्रेज के समय वे घर में अकेले थे। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अस्पताल के आईसीयू में रखा गया था। जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसकी जानकारी मिली थी तो वह भी उनका हाल-चाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। खरे के निधन की खबर मिलते ही मुंबई से उनके परिजन दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। उनकी मृत्यु पर साहित्य जगत से जुड़े बड़े लोगों ने अपनी संवेदना प्रकट की है।

30 जून को ही संभाला था अपना कार्यभार

ज्ञात हो कि दिल्ली सरकार ने उन्हें इसी साल हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्होंने 30 जून को ही अपना कार्यभार संभाला था। इससे पहले वह मुंबई में रहते थे, लेकिन गत दिनों दिल्ली हिंद अकादमी का उपाध्यक्ष बनने पर वह कुछ दिनों से दिल्ली ही रहने लगे थे। खरे लंबे समय तक एक प्रतिष्ठित समाचार-पत्र से जुड़े रहे और बाद में मुम्बई में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रहे थे। वह कवि के अलावा जाने-माने फिल्म समीक्षक, अनुवादक और प्रसिद्ध आलोचक भी रहे और बेबाक लेखन के कारण साहित्य के विवादों में भी फिरे रहे। हिंदी अकादमी की 18 सदस्यीय संचालन समिति के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं।



- नक्शे पर स्वयं और वास्तुकार के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करवाने होंगे,
- प्लॉट में ग्राउंड फ्लोर के रूप में कम से कम आधे हिस्से पर निर्माण होना अनिवार्य होना चाहिए
- निर्माण को लेकर गलत सूचना देने-सूचना छिपाने पर भारी जुर्माना

- मकान की सभी दिशाओं से लिए गए फोटो भी आवेदन के साथ लगाने होंगे

- अनिशमन विभाग ओर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियेंसी (बीईएफ) से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा

ग्रेनोप्रा के पूर्व जीएम के छह ठिकानों पर आयकर के छापे

ग्रेटर नोएडा में स्कूल, हॉस्टल, कामर्शियल प्रोजेज्ट, दादरी में बैंकट हॉल, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेज्ट समेत अकूत सज्पज़ि के कागजात बरामद

ग्रेटर नोएडा, एजेंसी। आयकर विभाग ने मंगलवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पूर्व महाप्रबंधक व भाजपा नेता रविंद्र तोंगड़ के आवास, स्कूल, हॉस्टल व पैतृक गांव समेत छह स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान अकूत सम्पत्ति के कागजात बरामद हुए हैं। तोंगड़ का ग्रेटर नोएडा में स्कूल, हॉस्टल, कमर्शियल प्रोजेक्ट, दादरी में बैंकट हॉल, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट समेत अकूत सम्पत्ति बताई गई है। तोंगड़ जब प्राधिकरण में महाप्रबंधक के पद पर तैनात थे उस समय भी आयकर विभाग का छाप पड़ा था। सूत्र बताते हैं कि तोंगड़ का दिल्ली व

देहरादून में भी कई प्रोजेक्ट हैं। नौकरी के दौरान रविंद्र के बसपा नेताओं से बहुत अच्छे संबंध थे। उस समय तोंगड़ को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में प्रॉपर्टी विभाग के अलावा अन्य कई विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। माना जा रहा है उसी समय तोंगड़ ने अकूत सम्पत्ति अर्जित की थी।

आयकर विभाग की कई टीमों मंगलवार को सुबह रविंद्र के सेक्टर बीटा-एक स्थित आवास, कौशल्या वल्ड स्कूल, हॉस्टल तथा पैतृक गांव आनंदपुर (दादरी के पास) पहुंची और छानबीन की। आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी था।

गुरुग्राम : अब 72 कॉलोनियों में अवैध निर्माण हो सकेगें वैध

गुरुग्राम। हरियाणा सरकार से लाइसेंस लेकर विकसित की गई रिहायशी कॉलोनियों में हुए अवैध निर्माण अब वैध होंगे। इसके लिए कब्जा प्रमाण पत्र लेकर आवेदन करना होगा। इसके बाद निर्माण को वैध कर दिया जाएगा। जिले की 72 कॉलोनी इसका लाभ उठा सकेंगी। प्रदेश सरकार की ओर से लाइसेंस लेकर जिले में 72 कॉलोनी विकसित की गई है। इनमें बड़ी संख्या में लोगों ने बिना नक्शा पास कराए निर्माण कर लिया है। ऐसे अवैध निर्माण को सरकार ने वैध करने का फैसला किया है। इसको लेकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से छह सितंबर को आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत बिना नक्शा पास कराए निर्माण करने वाले लोग कब्जा प्रमाण पत्र (ओसी) के लिए आवेदन कर सकेंगे। अधिकारियों की ओर से निरीक्षण किए जाने के बाद

ओसी देकर वैध कर दिया जाएगा। **अतिरिक्त निर्माण करने वालों को भी लाभ :**

विभाग से नक्शा पास कराने के बाद अतिरिक्त निर्माण करने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। ऐसे लोगों को अतिरिक्त निर्माण के चलते अभी तक ओसी नहीं मिल पाया है। अब लोगों को नक्शे की प्रति लगानी होगी। उसमें बताना होगा कि कितना अतिरिक्त निर्माण है। इसके बाद उसे वैध कराकर ओसी प्राप्त की जा सकेगी।

चार मंजिल से ऊपर लागू नहीं : यदि अवैध निर्माण चार मंजिल से अधिक हो तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। नियमों के मुताबिक भूतल के अलावा तीन फ्लोर और स्टिफ्ट भूतल के अलावा चार फ्लोर तक मान्य होगा। इससे अधिक मंजिल निर्माण पर उसे अवैध ही माना जाएगा।

हजारों परिवारों को मिलेगा लाभ प्रदेश सरकार की नई योजना का लाभ हजारों परिवारों को मिलेगा। इसमें डीएलएफ जैसी पॉश कॉलोनियों को मकान तक शामिल हैं। जहां पर नक्शे के अलावा बड़ी संख्या में अतिरिक्त निर्माण कर लिया गया। वहीं यहां के लोगों को हर रोज होने वाली तोड़फोड़ से भी निजात मिल सकेंगी। नक्शा पास कराए बिना किए गए निर्माण को वैध कराया जा सकेगा। मकान मालिक को विभाग में ओसी के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद मकान की जांच कर नियमों के मुताबिक पाए जाने पर ओसी दी जाएगी।

–अमित कुमार, एटीपी (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग)
आवेदक के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें
1. आवेदक को इमारत का नक्शा बनाकर जमा करवाना होगा। अवैध निर्माण को चिह्नित करना होगा।

मैं सफलता की प्रार्थना नहीं करती हूं, मैं विास के लिए कहती हूं -मदर टेरेसा

विलय की घोषणा

बैंक ऑफबड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक के विलय की घोषणा कर दी है। विलय का तर्क दिया जा रहा है कि एक कमजोर बैंक को दो अपेक्षाकृत मजबूत बैंक मिलकर संभाल लेंगे। इन बैंकों में सबसे मजबूत स्थिति में विजया बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी बुरी स्थिति में नहीं है। देना बैंक की स्थिति बहुत खराब है। इतनी खराब है कि यह रिजर्व बैंक की नियमित निगरानी में है। इसका शुद्ध ड्रबत कर्ज अनुपात 11.04 प्रतिशत है यानी इसके द्वारा दिए गए कजरे का करीब 11 प्रतिशर डूबने की स्थिति में है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मामले में यह आंकड़ा 5.40 प्रतिशत विजया बैंक के मामले में 4.10 प्रतिशत का है यानी सबसे कम डुबाऊ स्थिति में विजया बैंक है। पर विजया बैंक अब डूबते बैंक के साथ नत्थी कर दिया है। विजया बैंक का शेयर आज 7.26 प्रतिशत गिरकर बंद हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर यानी विजया बैंक पर निवेशकों को आशंकाएं हैं कि यह बैंक भी अब खस्ताहाली में पहुंच सकता है। यह आशंका निराधार भी नहीं है। देना बैंक की खस्ताहाली संभालते संभालते कहीं विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और देना बैंक से बना नया बैंक भी खस्ताहाली में ना गिर जाए। सरकार के लिए तो काम आसान हो जाएगा कि कई बैंकों की खस्ताहाली पर आलोचना सुनने के बजाय एक ही बैंक के डूबने पर आलोचना सहनी पड़ेगी। पर सवाल यह है कि क्या यह विलय उन समस्याओं का समाधान कर पाएगा, जो विजया बैंक को घेरे खड़ी थीं। इस सवाल का जवाब है नहीं। बिल्कुल नहीं। दावे किए जा रहे हैं कि इन बैंकों के विलय से जो नया बैंक बनेगा वह देश का तीसरा बड़ा बैंक होगा। साइज में बड़े होने से ही सब कुछ नहीं होता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है, पर क्या वह सबसे कुशल बैंक भी है? इस सवाल का जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकारी बैंकों की कार्यसंस्कृति में आमूल चूल बदलाव लाने की जरूरत है, और यह भी यहां रेखांकित किया जाना चाहिए। रिजर्व बैंक के रघुराम राजन ने इशारा किया है कि मुद्रा कजरे के नाम, किसानों को सस्ते कर्ज के नाम पर जो कर्ज दिए गए हैं, उनमें भी डूबत कर्ज आने की आशंकाएं हैं। अगर साइज के आधार पर बैंकिंग सफलताएं तय होतीं, तो देश का सबसे कामयाब बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता।

स्वयंसेवक संघ

स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित तीन दिवसीय संवाद कार्यक्रम के पहले दिन परसंघचालक मोहन भागवत ने संगठन के बारे में जितना विस्तार से बताया, लगने वाले आरोपों का जिस तरह जवाब दिया, उन सबसे काफी धुंध छंटनी चाहिए। किंतु, ऐसा लगता नहीं कि जो संगठन, नेता, बुद्धिजीवी..संघ का केवल विरोध करने या उस पर आरोप लगाने का ही मांस बनाए हुए हैं, उनके विचार परिवर्तित होंगे। हालांकि संघ की कोशिश यही थी कि हमारे विरोधी भी कार्यक्रम में आएँ, हमारी बात सुनें, अपनी बात रखें, हमसे प्रश्न करें। लोकतांत्रिक समाज में परस्पर विरोधी विचारों के बीच भी संवाद चलते रहना चाहिए। दुर्भाग्य से किसी प्रमुख राजनीतिक दल के नेता या घोर विरोधी माने जाने वाले बुद्धिजीवी नहीं पहुंचे। यह कैसा लोकतांत्रिक संस्कार है? भागवत ने कहा कि संघ का हिन्दू समाज को संगठित करने का संकल्प किसी मत का विरोध करना नहीं है। वह मानता है कि भेदरहित, स्वार्थमुक्त समाज ही स्वतंत्रता और स्वतंत्र राष्ट्र के परमवैभव की गारंटी है।

भागवत ने कहा कि भारतीय समाज विविधताओं से भरा है, किसी भी बात में एक जैसी समानता नहीं है, इसलिए विविधताओं से डरने के बजाए उन्हें स्वीकार करना और उनका उत्सव मनाना चाहिए। उन्होंने इस आरोप का भी जवाब दिया कि संघ राजनीतिक सत्ता हथिया कर देश पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। संघ का उद्देश्य सफल राष्ट्र के लिए सुयोग्य समाज का निर्माण है। भागवत ने यह भी साफ किया कि संघ मानता है कि समाज को बदले बिना स्थायी परिवर्तन नहीं आ सकता है।

देश के लोगों में देश के प्रति विास पैदा करने की आवश्यक है, और इसके लिए लोक शक्ति का जागरण करना पड़ेगा। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय तिरंगे को लेकर संघ के विषय में प्रचलित भ्रांतियों को भी दूर करने का प्रयास किया।

इस दृष्टि से देखें तो संघ प्रमुख ने अपना पूरा मत देश के सामने स्पष्ट कर दिया है तथा लोगों से निकट आकर संगठन को समझने की अपील भी की है। यह समझ से परे है कि आखिर, संघ की बात सुनने, उस पर विचार करने तथा वहां अपनी बात रखने में किसी को क्या समस्या हो सकती है। बहरहाल, भागवत की बातें मीडिया के माध्यम से बहुत लोगों के पास पहुंचेंगी और वे फैसला करेंगे कि संघ के प्रति कैसा दृष्टिकोण बनाना चाहिए।

सत्संग

“धरती मां”

पृथ्वी को “ धरती मां ” कहते हैं। क्या इसका मतलब है कि धरती पर सारा अपराध रुक जाएगा? नहीं। अलग-अलग तरह के अपराध होते हैं। स्त्रियों पर यौन हमले बहुत आम हैं। इसके कई पहलू हैं। हम गुस्से में आकर बोल सकते हैं, “ ठीक है, उन्हें फांसी दे दो। ’ अगर आप बलात्कार की सजा के तौर पर फांसी को लाएंगे तो आपको समझना चाहिए कि बलात्कार के मामले में एकमात्र गवाह लगभग हमेशा पीड़िता होती है। अगर आप एक बलात्कारी को इस बात की गारंटी दें कि बलात्कार करके पकड़े जाने पर तुम्हें फांसी लगनी तय है, तो आपके ख्याल से वह क्या करेगा? वह उस एकमात्र गवाह को रास्ते से हटा देगा। तो कुछ कहने से पहले हमें सतर्क रहना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनका समर्थन कर रहे हैं। सवाल बस यह है कि आपको समाधान चाहिए या कंगारू कोर्ट : “हर किसी को फांसी पर लटका दो। ’ हमें देखना चाहिए कि यह हो क्यों रहा है। पहली चीज यह है कि एक संस्कृति के रूप में भारत के लिए यह पहली पीढ़ी है, जिसमें स्त्रियां वास्तव में सड़क पर निकल रही हैं, पुरुषों के साथ चल रही हैं, और उनके करीब रह कर काम कर रही हैं। लोगों को इसकी आदत नहीं है। साथ ही लाखों युवा गांवों से शहरों में आ रहे हैं। उनके गांव में उनके लिए स्त्री का मतलब उनकी मां, उनकी मौसी, अत्ते या घाटी (बुआ या दादी) होती थी। अब वे शहर आकर युवा लड़िकयों को सड़क पर चलते देखते हैं। यह उनके लिए बहुत नया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि चीजों को अनदेखा कर दें और ऐसा दिखाएं मानो, हम कहीं से टपके हैं। ईसानों में सेक्सुअलिटी या यौनिकता होती है। पंद्रह से पच्चीस की उम्र के बीच हार्मोन का असर अधिकतम होता है। अगर आपको व्यस्त रखने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फआपके हारमोन आपके भीतर उछल रहे हैं तो सामाजिक स्तर पर इसका हल खोजना होगा। जब कोई अपराध करता है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए, यह अलग मामला है। मगर सामाजिक तौर पर इसका क्या हल है?

संपादकीय

संगठनों की जीत के संकेतों

राजस्थान की राजनीतिक गतिविधियों के बीच दलित छात्र की जीत राज्य में बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत है। राजस्थान के अन्य संस्थानों में भी वामपंथी पार्टियों से जुड़े छात्र संगठनों ने चुनावी जीत हासिल की है। सत्ताधारी भाजपा-आरएसएस विचारधारा के छात्र संगठन और समूहों ने भी दिल्ली विविद्यालय में जीत हासिल की है, और यह विविद्यालय हमेशा से संघ का गढ़ माना जाता रहा है। छात्र राजनीति में हाल के वर्षों में जो हलचल दिखाई दे रही है, उससे भविष्य की राजनीतिक तस्वीर का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इन तमाम विविद्यालयों में जेएनयू अलग अहमियत रखता है। कहा जा सकता है कि इसे एक प्रतीक के रूप में रचने की कोशिश की गई है।

सतीश पेडणोकर

छात्र संघ चुनाव में वामपंथ से जुड़े छात्र संगठनों की जीत के संकेतों को समझने की जरूरत है। हाल के दिनों में देश के विभिन्न राज्यों में स्थित विविद्यालयों के छात्र संघों के चुनाव हुए हैं, और उनमें गैर आरएसएस पार्टियों से जुड़े और उसके विरोधी छात्र नेतृत्व को जीत मिली है। बल्कि कहा जाए कि इस संदर्भ में ऐतिहासिक घटनाएं सामने आई हैं। पंजाब विविद्यालय देश के सबसे पुराने विविद्यालयों में शुमार है, और वहां पहली बार एक लड़की ने जीत हासिल की है। राजस्थान विविद्यालय में पहली बार एक दलित छात्र बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीता है। राजस्थान की राजनीतिक गतिविधियों के बीच दलित छात्र की जीत राज्य में बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत है। राजस्थान के अन्य संस्थानों में भी वामपंथी पार्टियों से जुड़े छात्र संगठनों ने चुनावी जीत हासिल की है।

सत्ताधारी भाजपा-आरएसएस विचारधारा के छात्र संगठन और समूहों ने भी दिल्ली विविद्यालय में जीत हासिल की है, और यह विविद्यालय हमेशा से संघ का गढ़ माना जाता रहा है। छात्र राजनीति में हाल के वर्षों में जो हलचल दिखाई दे रही है, उससे भविष्य की राजनीतिक तस्वीर का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इन तमाम विविद्यालयों में जेएनयू अलग अहमियत रखता है। कहा जा सकता है कि इसे एक प्रतीक के रूप में रचने की कोशिश की गई है, और इसके बहाने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए उपयुक्त विमर्श खड़ा करने में सहूलियत महसूस की जाती है। जेएनयू को एक विचारधारा के प्रतीक के रूप में खड़ा किया गया और यह ऐसा संस्थान है जिसकी छवि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पूरे आडंबर को बाधित करने वाले विचारों की धुरी के रूप में विकसित होती दिखती है। छात्र संघ के चुनाव नतीजों पर बात करने के लिए जेएनयू के सत्ताधारी विचारधारा के लिए महत्त्व को इस उदाहरण से भी समझा जा सकता है।

गुजरात में 2002 के मुस्लिम विरोधी हमले की घटनाओं को रोकने के सिलसिले में आईपीएस अधिकारी आरबी श्रीकुमार का तब के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के रवैये को लेकर मतभेद रहा है। उन्होंने 2002 के दौरान की तमाम घटनाओं और मुख्यमंत्री के साथ पुलिस अधिकारियों की बैठकों और निर्देशों का अपनी पुस्तक “गुजरात बिहाइंड करटेन” में उल्लेख किया है। इसी कड़ी में 25 जून, 2002 को राज्य के वरिष्ठ पुलिस कर्मियों के साथ मुख्यमंत्री की एक बैठक के बारे में भी जानकारी दी है।

श्रीकुमार ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 127 पर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में नरेन्द्र मोदी द्वारा जेएनयू पर की गई एक टिप्पणी का उल्लेख किया है। जब पुलिस अधिकारी राज्य सरकार के बतौर मुखिया नरेन्द्र मोदी के विचारों से अपना अंतर्विरोध जाहिर कर

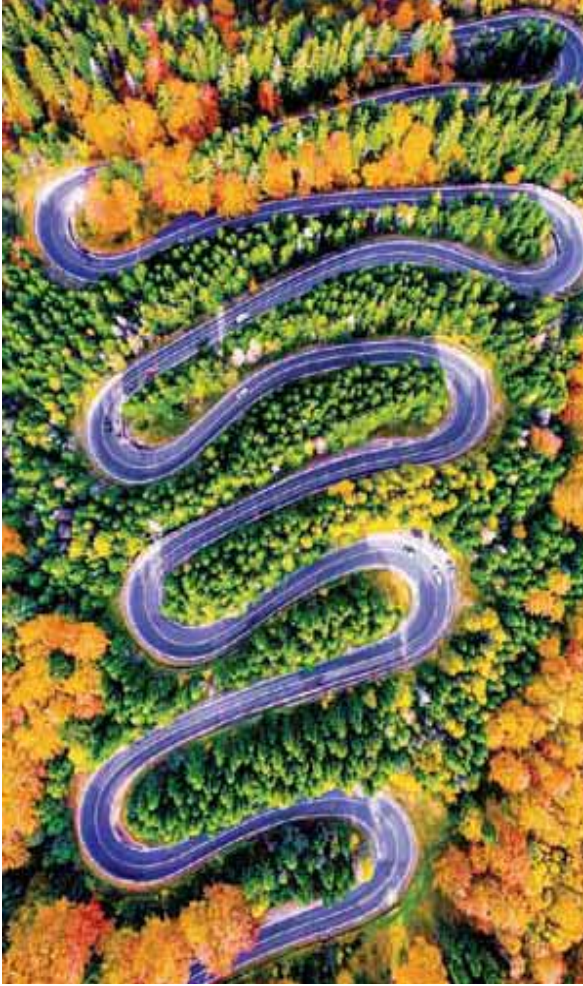
चलते चलते

हिंदी टीवी चैनल

बहुत अच्छा था चचा! कल उनका एक सौ बाराहवां जन्मदिन भी था और प्रयाण दिन भी। लगभग सभी हिंदी टीवी चैनल कल उनको याद करती रहीं। जगह-जगह उनकी स्मृति में गोष्ठियां हुईं। हाथरस में उनके स्मारक पर हाथरस वासियों ने उनकी कविताओं का पाठ किया। हमने भी जयजयवंती फाउंडेशन में “हास्य-महर्षि काका हाथरसी” पर संगोष्ठी आयोजित करी। –तौ का कियो? –अरे, काका जी की कविताएं सुनाई गईं, संस्मरण सुनाए गए, टहाके लगे। मुझे उनकी कुछ शोधपूर्ण लम्बी कविताएं बड़ी पसंद हैं। इन दिनों हिंदी पखवाड़ा भी चल रहा है। उनकी “नाम बड़े और दर्शन छोटे” कविता सुनाई, आज भी प्रासंगिक है। –तौ सुनाय दे नैक-आध। –उस कविता में छः-छः पक्तियों के सोलह छंद हैं। चलिए, आपको हाथरस में उनके स्मारक पर हाथरस वासियों ने उनकी कविताओं का पाठ किया। हमने भी जयजयवंती फाउंडेशन में “हास्य-महर्षि काका हाथरसी” पर संगोष्ठी आयोजित करी। –तौ का कियो? –अरे, काका जी की कविताएं सुनाई गईं, संस्मरण सुनाए गए, टहाके लगे। मुझे उनकी कुछ शोधपूर्ण लम्बी कविताएं बड़ी पसंद हैं। इन दिनों हिंदी पखवाड़ा भी चल रहा है। उनकी “नाम बड़े और दर्शन छोटे” कविता सुनाई, आज भी प्रासंगिक है। –तौ सुनाय दे नैक-आध। –उस कविता में छः-छः पक्तियों के सोलह छंद हैं। चलिए, आपको

लिखें शराब, दया हमको आएगी, “हरीवंश त्यागी” की “हत्था” हो जाएगी। बदल जाएं उपनाम, होयें मानी-बेमानी, कहलाएं ‘गोपालदास नीरज’ “गोदानी। ’” चचा, गोदानी तक तो गनीमत है, ईर दत्त “ईद’ कहलाएं ये भी चलेगा, लेकिन लीला दत्त तो “लीद’ हो जाएंगे। तेजपाल लीडर “तेली’, होती लाल “होला’, छोटे लाल “छोला’, कहलाएंगे। लगभग पचास साठ नाम हैं कविता में। एक लंबा नाम है, नारायण लाल यतींद्र कथक्कड़, इसका संक्षिप्त होगा “नालायक’। अंत में काका कहते हैं, “जानबूझकर स्वयं ही क्यों होते बदनाम? उतना दुखदायी बने जितना लम्बा नाम। जितना लम्बा नाम, रखो छोटे-से-छोटा, दो क्षअर से अधिक नाम होता है खोटा। सूक्ष्म नाम पर कभी नहीं पड़ सकता डाका, उल्टो-पल्टो, शॉर्ट करो, फिर भी हैं ‘काका। ’ –मान गए लल्ला! अमर रहें काका!

फोटोग्राफी...



रोमानिया की ट्रान्सिल्वेनिया घाटी, जो हर मौसम में अलग-अलग रंग बदलती है

यह फोटो रोमानिया की मशहूर ट्रान्सिल्वेनिया घाटी की फोटो है, जिसे वहीं के एरियल फोटोग्राफर कालिन स्टैन ने क्लिक किया है। उन्होंने बताया कि इसी क्षेत्र की मैंने लैंडस्केप फोटोग्राफी की थी, लेकिन इस दृश्य के लिए पतझड़ आने का इंतजार किया। कुछ दिनों पहले कालिन वहां पहुंचे और उन्होंने विभिन्न रंगों वाली घाटी का यह फोटो क्लिक किया। ऐसा इसलिए क्योंकि पतझड़ में यहां के पेड़ों का रंग बदलने लगता है। इस घाटी को काउंटे झकुला भी कहा जाता है। कालिन कहते हैं, रोमानिया में बहुत ज्यादा हाईवे नहीं हैं। नया हाईवे बनने के बाद लोग इस हाईवे को भी भूल जाएंगे, लेकिन मैं यहां के दृश्यों को यादगार बनाना चाहता हूं। उन्होंने इसी वादी के चार मौसम में अलग-अलग फोटोग्राफ क्लिक करके उन्हें ‘इन्फाइनाइट रोड टू ट्रान्सिल्वेनिया’ में शामिल किया है। हर मौसम में यहां का रंग अलग होता है, सर्दियों में बर्फबारी के कारण सफेद तो बारिश के दिनों में पूरी तरह हरा। dronestagr.am

क्रांति समय

संकेत

संकेत

संकेत

संकेत

संकेत

संकेत

संकेत



सकती है, जो खास तरह की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि की सीमाओं के साथ प्रवेश करते हैं, लेकिन उच्च शिक्षण संस्थानों में बौद्धिक विमर्श में परिपक्व होते छात्र-छात्राओं के बीच अपनी स्वीकृति बनाना ही छात्र संगठनों की उपलब्धि के तौर पर माना जाता है। सत्ता मशीनरी का इस्तेमाल और दुरुपयोग छात्रों में प्रतिक्रिया ही व्यक्त करता है।

विविद्यालय को अपनी वैचारिकी ताकत से बदलने में अक्षमता उन हालात को विकसित करने की तरफले जाती है, जेएनयू पहुंच रहा है। वामपंथी छात्र संगठनों की जीत अगले आम चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ एक मोर्चा बनाने के लिए दबका संकेत से भरा संदेश है। देश भर में सत्तारूढ़ दलों के छात्र संगठनों के खिलाफ शिक्षण संस्थानों में जिस तरह से मत प्रगट किए जा रहे हैं, उन्हें संसदीय लोकतंत्र में परिवर्तन की आहट के रूप में चिह्नित किया जा सकता है।

“फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स

जिस दूध का सेवन कर रहे हैं, क्या पीने योग्य है? संभवतः नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने हाल में भारत सरकार को एक एडवाइजरी भेजी है। इसमें कहा गया है कि भारत में मिलावटी दूध और उसके उत्पादों पर तत्काल रोक न लगाई गई तो साल 2025 तक भारत की 87 फीसद जनसंख्या कैंसर जैसे जानलेवा रोगों की गिरफ्त में होगी। सरकार ने लोक सभा में 17 मार्च, 2015 को माना था कि देश में बिकने वाला 68 फीसद दूध दूषित ही होता है। दूध में मिलावट की बाबत एक सर्वे से पता चला है कि उत्तर भारत के राज्यों में मिलावटी दूध देश के बाकी भागों या राज्यों की तुलना में अधिक बिक रहा है। जहरौला दूध आंख से लेकर आंत तक, दिल से लेकर प्रजनन क्षमता तक, सब पर असर डालता है। इनसान टाइफाइड, पीलिया, अल्सर, डायरिया जैसी बीमारियों की चपेट में भी आ सकता है। उच्चतम न्यायालय ने दूध में मिलावट को रोकने के लिए साल 2015 में एक अहम फैसला सुनाया था। माना था कि देश में मिलावटी दूध बिक रहा है, और कानून में कड़े प्रावधान करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने निर्देश दिए थे कि केंद्र और राज्य सरकारों “ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ट्स एक्ट 2006’ को सख्ती से लागू करें। इस निर्देश का किस हद तक पालन हुआ? नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? कौन जवाब देगा इसका? यहां पर यह भी समझना आवश्यक होगा कि दूध उत्पादन को बढ़ाने का लाभ ही क्या है, अगर हम मिलावटी दूध का कारोबार न रोक पाएं। यह तो हुई 68ब मिलावटी दूध की बात। अब जरा, बाकी के 32% की भी बात कर लें। इनमें भी अधिकांश दूध जर्सी, होलिस्टियन, फ्रीजियन आदि दोगली किस्म की गायों का है, जो वास्तव में गाय हैं ही नहीं। इन पर प्रकाशित शोध पत्रों के मुताबिक, इन गायों (या पशुओं का) के दूध, जिसे “ए-1’ की संज्ञा दी जाती है, में “बीटा मारफीन’ नाम का जहर है जो डाइबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, मानसिक रोग और गर्भस्थ शिशुओं में होने वाली मानसिक या शारीरिक विकलांगता, जिसे “ऑटिज्म’ कहा जाता है, जैसी पांच बड़ी बीमारियों का मुख्य कारण है। आधुनिकतम रिसर्च यह है कि विश्व भर में भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में पाई जाने वाली देसी गाय का दूध ही, जिसे “ए-2’ नस्ल की गाय की संज्ञा अंग्रेजों ने दे रखी है, मां के दूध के समान है। “ए-2’ नस्ल की गाय की सामान्य पहचान “कंधे पर उभार या पुड़ा’ और गले के नीचे का झालर है। दुर्भाग्यवश ऐसी अधिकांश गायें अब तो ज्यादातर ब्राजील, कनाडा, अमेरिका, स्विटजरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हमने निर्यात कर दी हैं, और विदेशों से ज्यादा दूध के नाम पर दोगली गायों को ले आए हैं, जिनके दूध में “बीटा मारफीन’ होता है यानी अब विदेशी हमारी “गौ माता’ का दूध पी रहे हैं, और हम जहर पीने को मजबूर हैं। बता दें कि भैंसों का दूध भी “ए-2’ होता है यानी वह पानी मिलाकर पतला करके पीने लायक तो है, लेकिन, सुपाच्य नहीं है क्योंकि “ए-2’ यानी देसी गायों के दूध का “मैल्टिंग तापमान’ 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि मनुष्य के शरीर का तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे “ए-2’ गाय का दूध अमाशय में जाते ही पच जाता है, जबकि भैंस के दूध का मैल्टिंग तापमान 40 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः भरपूर शारीरिक परिश्रम न किया जाए तो इसे पचाने में परेशानी होती है, जिससे उसकी चर्बी धमनियों में जमा हो जाती है और हृदय रोग का कारण बन जाती है। कहना है कि दूषित दूध की बिक्री पर रोक लगाए बिना बात नहीं बनेगी। सांकेतिक करम उठाने का वक्त निकल चुका है। तय कर लीजिए कि देश को स्वस्थ देखना चाहते हैं, या बीमार।

जुडिशल काउन्सिल ने की ग्रीन इंडिया डे की शुरुवात

भारत के इतिहास में जुडिशल काउन्सिल ने 18 सितम्बर को भारत के विभिन्न शहरों में ग्रीन इंडिया डे मना कर मील का पत्थर खड़ा कर दिया, ग्रीन इंडिया डे का नाम दिया है जुडिशल काउन्सिल नामक एनजीओ ने, ग्रीन इंडिया डे की भारत को हर भरा बनाने की यह मुहीम जारी रहेगी और हर वर्ष 18 सितम्बर को यह दिन ग्रीन इंडिया डे के रूप में मनाया जायेगा सिर्फ यही नहीं ग्रीन इंडिया डे जुडिशल काउन्सिल की मुहीम के अंतर्गत स्कूलों, कालेजों, सार्वजनिक स्थल तथा हर वह जगह जहाँ यह लगता है की हरियाली की जरूरत है उस स्थान पर हरियाली के लिए पौधा लगाया जायेगा भारत सरकार तथा दिल्ली सरकार को पत्र तथा ईमेल के माध्यम से सरकार से गुजारिश की गयी है की दिल्ली में रिज रोड एरिया में रैन्फोरेस्ट बनाया जाये जो आज के समय की जरूरत है हम सभी तथा विश्व में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे तथा अर्थ डे मनाया जाता है, परंतु आज तक भारत ने ग्रीन डे नहीं मनाया, और आज जुडिशल काउन्सिल इस की पहल कर रहा है बढ़ते हुए प्रदुषण तथा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए आज पर्यावरण की सुरक्षा हर आम आदमी की जरूरत है अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आदमी को जिन्दगी भर दवाओं पर

आश्रित रहेगा पड़ेगा, ग्रीन इंडिया डे दिल्ली के अलावा विभिन्न शहरों में मनाया गया प्रमुख शहरों में अमृतसर, कोलकाता बंगलोर, कानपुर, लखनऊ, धनबाद मुख्य रहे इस अवसर पर बोलते हुए जुडिशल काउन्सिल के डायरेक्टर जनरल श्री राजीव अग्रिहोत्री ने कहा ? आज किसी भी प्लांटेशन ड्राइव का उद्देश्य, पर्यावरण से लड़ना है पर यह उद्देश्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक सब का साथ निरंतर न हो और सरकार को चाहिए की वोह सिर्फ दिखाने के लिए पेड़ पौधे नालगाये वरन वो लोगों में इसका मोह जगाये, इसके लिए रैन्फोरेस्ट को तैयार करे तथा कुछ स्थानों को रैन्हाबिलीटिंग के रूप में विकसित करें जिस से पौधों को प्रयाप्त मात्रा में पानी मिल सके और कड़ी गर्मी में भी पानी की किल्लत न हो, रेन फारेस्ट तैयार करना थोड़ा मुश्किल होगा क्यों की वहाँ पर पानी की लगातार व्यवस्था होनी चाहिए, ग्रीन इंडिया डे के अवसर पर पेड़ पौधे लगाये गए तथा आम नागरिकों को पेड़ पौधे बांटे भी गए ग्रीन इंडिया डे की महत्त्वता पर बोलते हुए श्री अग्रिहोत्री ने कहा इसकी शुरुवात 18 सितम्बर को जरूर हो रही है पर ग्रीन इंडिया की मुहीम सतत जारी रहेगी श्री अग्रिहोत्री ने



बताया बहुत ही जल्द इस स्थान पर जहाँ आज पेड़ पौधे लगे हैं, फलों के पौधे भी लगाये जायेंगे जिसका का इस्तेमाल पशु पक्षी कर सकें, ग्रीन इंडिया डे में आज जहाँ वकीलों, जुडिशल काउन्सिल के वालंटियर तथा आम आदमियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. इस अवसर पर अपील करते हुए जुडिशल काउन्सिल के डायरेक्टर जनरल श्री अग्रिहोत्री ने कहा जन्म दिन पर केक काटें पर रीटर्न गिफ्ट में भेंट स्वरूप पौधा ही दे साथ ही अपने जन्म दिन पर कम से कम एक पौधा लगाये अधिवक्ता विजय ने यह खुशी जाहिर की, कि ग्रीन इंडिया डे में

उनको भी हिस्सा लेने का मौका मिला और जुडिशल काउन्सिल और जुडिशल काउन्सिल के डायरेक्टर जनरल श्री राजीव अग्रिहोत्री को बहुत धन्यवाद दिया तथा कहा आज से मैं अपने जन्म दिन पर पौधा जरूर भेंट दूँगा. तथा जो भी मेरे मित्र हैं उनसे भी आग्रह करूँगा की पौधा अवश्य भेंट करें तथा हर वर्ष 18 सितम्बर को ग्रीन इंडिया दे के रूप में मनाएं जुडिशल काउन्सिल के स्वयं सेवक बहुत जल्द खुद स्कूलों, कॉलेजों, कारखानों, सार्वजनिक स्थल तथा अस्पतालों में जा कर वहाँ पौधा रोपण करेंगे।

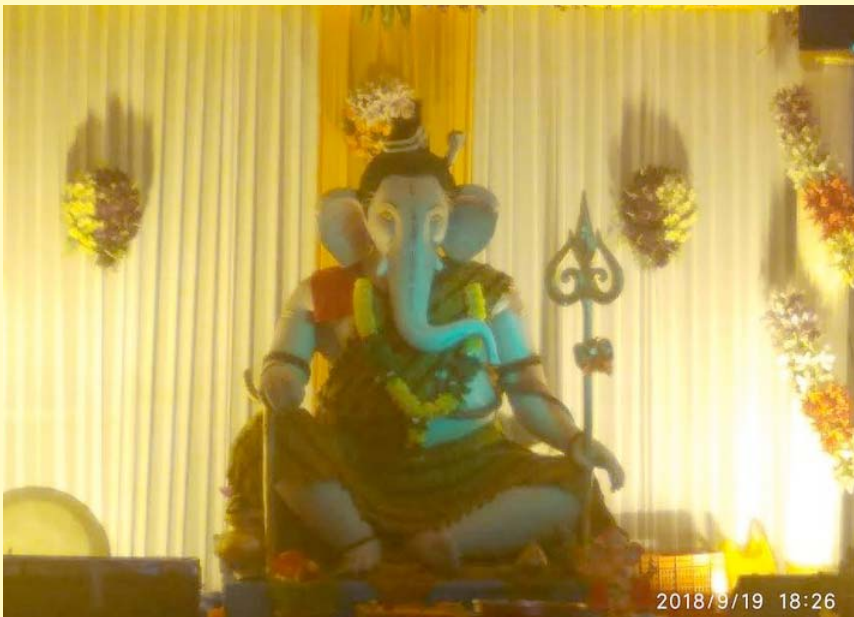
गणपति बप्पा मोरिया.....



साई नाथ सोसायटी कनकपुर कनसाड, सचिन।



साई नाथ सोसायटी कनकपुर कनसाड, सचिन।



गणेश नगर पांडेसर सूरत।

वीर तेजा जी महाराज की निकली भव्य शोभायात्रा



सूरत। विश्व हिन्दु परिषद गौ रक्षा आंदोलन समिति के तत्वाधान में बुधवार की सुबह डी. आर. वर्ल्ड पर्वत पाटिया से राजस्थान जाट समाज भवन पर्वत पाटिया तक वीर तेजा जी महाराज की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस शोभायात्रा में विभिन्न हिन्दु संगठनों के अग्रणियों तथा गौ रक्षकों एवं गौ भक्तों ने भाग लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य आयोजक एवं विश्व हिन्दु परिषद गौ रक्षा आंदोलन समिति के प्रांत संयोजक नरेन्द्र चौधरी, ओम प्रकाश चौधरी, राजस्थान जाट समाज के अध्यक्ष केलाश जी बेनीवाल, दिनेश जी बाबल, बाबुलाल खादव, विक्रम सेखावत, महेंद्र सिंह राजपुरोहित, विजय चोमाल, रामनिवास बिस्, पान्नाराम जी ढाडिया ने शोभायात्रा की अगुवानी की इस अवसर पर इश्वर बेनीवाल (मुन्ना भाई) मौजूद रहे। ये रैली डी. आर. वर्ल्ड पर्वत पाटिया से निकल कर राजस्थान जाट भवन पर्वत पाटिया पहुंची।

शराबबंदी के चुस्त अमल के लिए सरकार कटिबद्ध

अहमदाबाद। गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदिपसिंह जाडेजा ने आज एकबार फिर कहा कि शराबबंदी के चुस्त अमल के लिए राज्य सरकार संपूर्ण रुप से प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य परमिट रखनेवाले लोगों के लिए नये कड़े नियम भी घोषित किये गये हैं। गुजरात विधानसभा में नियम ४४ के तहत नये नियम की घोषणा प्रदिपसिंह जाडेजा की ओर से की गई। जिसके चलते राज्य में २६ एरिया मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था रह कर दी गई है। नये छह एरिया मेडिकल बोर्ड बनाये गए हैं। नीजि डॉक्टर के प्रमाणपत्र की व्यवस्था भी रह कर दी गई है। दूसरी और राज्य मेडिकल बोर्ड की पुनःरचना की गई है। विधानसभा में नये नियम घोषित करते हुए प्रदीपसिंह जाडेजा ने बताया कि मुख्यमंत्री रुपानी ने शराबबंदी के चुस्त अमल के लिए खास ध्यान केन्द्रित किया है। इसके अलावा कड़ी कार्यवाई भी शुरू की है।

जाडेजा ने बताया कि गत वर्ष विधानसभा सत्र में

नशाबंदी व्यवस्था में सुधार करते हुए कानून की और अधिक कड़ा बनाया गया था। जिसके बहुत से सारे परिणाम मिले हैं। हेल्थ आधारित परमिट लेने वाले जिसके चलते परमिट धारको की संख्या में भी नियंत्रण लाने का राज्य सरकार ने निर्धार किया है। नये नियम के तहत हेल्थ परमिट हांसिल करने के लिए अबतक अर्जीदार को अर्जी के साथ निजी डॉक्टर का प्रमामपत्र रखना पड़ता था। इस व्यवस्था को अब खतम कर दी गई है। अब निजि डॉक्टर का प्रमाणपत्र नहीं चलेगा। एरिया मेडिकल बोर्ड में सुप्रीटेन्डेन्ट स्तर के अधिकारी के अभिप्राय के आधार पर परमिट मिलती है। इसके बदले नये एरिया मेडिकल बोर्ड के आधार पर नई परमिय मिलेगी या नहीं यह बात नक्की होगी। जाडेजा ने कहा कि हेल्थ परमिट हांसिल करने के राज्य में २६ एरिया मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था की गई है।



सूरत। सूरत में लारी गल्ला चलाने वाले ने निकाली एस.एम.एसी के खिलाफ विशाल रैली। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। लारी गल्ले चलाने वालों की एस.एम.एसी द्वारा आये दिन लारी गल्ला उठा कर परेशान करे के खिलाफ रैली निकाली गई। लारी गल्ले चलाने वालों का कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में इस तरह की रैली निकाली जाएगी।

मंत्रियों का वेतन अब १,३२,०००, विधायको का वेतन १,१६,००० मंत्री और विधायकों के वेतन में हुई बढोतरी वेतन वृद्धि दिसंबर २०१७ से लागू होगी : विधानसभा में गुजरात वेतन भत्ता संशोधन विधेयक २०१८ पेश किया गया : जाड़ेजा ने घोषणा की

अहमदाबाद। गुजरात विधानसभा के सदस्यों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, विरोध पक्ष के नेता समेत सतेचकों के वेतन और भत्ते में बढोतरी की गई है। गुजरात में मंत्रियों और विधायको का वेतन बढ़ गया है। गुजरात में मंत्रियों का वेतन अब १,३२,००० रुपये और विधायको का वेतन अब १,१६,००० रुपये हो गया है। आज गुजरात विधानसभा में विधायक और मंत्रियों की वेतन वृद्धि से संबंधित विधेयक सर्वसंमति से पारित हो गया। वेतन वृद्धि दिसंबर २०१७ से लागू होगी। गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदिपसिंह जाडेजा ने गुजरात वेतन भत्ता संशोधन विधेयक २०१८ को संसद में पेश किया। राज्य के विधायको का वेतन पहले ७०,७२७ रुपये था वह अब बढ़कर १,१६,३१६ परमिय मिलेगी या नहीं यह बात नक्की होगी। जाडेजा ने कहा कि हेल्थ परमिट हांसिल करने के राज्य में २६ हजार रुपये की बढौतरी की गई है

। मंत्री, सचेतक आदि का वेतन ८६८०४ से बढ़ाकर १३२३१५ कर दिया गया है। इसी तरह विधायको का दैनिक भत्ता २०० रुपये से बढ़ाकर १००० रुपये कर दिया गया है। विधायको और मंत्रियों को सरकार करीब साढे छह करोड रुपये का एरियर देगी। वेतन वृद्धि से सरकार की तिजोरी पर १० करोड का अतिरिक्त बोझ पडेगा। विधानसभा की ओर से बढ़ाया गया वेतन सदस्यो को दिसम्बर २०१७ से मिलेगा। इस बीच कांग्रेस के विधायक विरजी तुम्नर ने विधायकों के गरीब ४३,००० तथा मंत्रियों के वेतन वृद्धि करीब ४५ हजार को भी ना काफी बताया है। कांग्रेस के ही दुसरे विधायक प्रतापसिंह ने संसद के बाहर आखिर कहा की जबतक राज्य में किसान के कर्ज माफ नहीं होंगे वे वेतन हो गया है। विधायको के वेतन में करीब ४० हजार रुपये की बढौतरी की गई है

ने वेतन वृद्धि का विरोध नहीं किया है। गुजरात विधानसभा के सदस्यों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्रियों, विरोध पक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते में बढौतरी कर दी गई है। इससे संबंधित संशोधन विधेयक २०१८ को प्रस्तुत करते हुए प्रदीपसिंह जाडेजा ने कहा कि देश के अन्य राज्यों की विधानसभा के विधायको समेत सचेतकों की तुलना में गुजरात विधानसभा के सदस्यो और सतेचकों को मिलनेवाले पगार और भत्ते कम है। साल २००५ से उसमें कोई भी बढौतरी नहीं की गई है। विधायको ने जनसंपर्क कामगोरी के संबंध में लगातार प्रवास किये है। जिसके चलते खर्च में बढौतरी हुई है। पगार-भत्ते में बढौतरी जरुरी बन गई थी। राज्यमंत्री प्रदिपसिंह जाडेजा ने संशोधन विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा कि विधायको ने राज्य सरकार के उपसचिव को मिल रहे

न्युनतम मूलभूत वेतन के बदले नायब सचिव के स्तर में मिलने वाले पगार को लेकर बात की थी। जिसके चलते अब विधायको को उपसचिव के समकक्ष पगार मिलेगा। गुजरात के विधायकों को इन दिनों प्रति महिने ७०७२७ रुपये पगार भत्ते के रुप में मिलते है। सूचित संसोधन के तहत अब विधायको, मंत्रियों और सचेतको को अधिक पगार मिलेगा। उत्तराखंड में विधायको का वेतन सबसे अधिक है। दुसरे नंबर पर तंलागणा और तिसरे नंबर पर झारखंड है। राजस्थान में विधायको को वेतन भत्ते के रुपये १३०००० रुपये मिलते है। महाराष्ट्र में २१३१३० रुपये मिलते है। विरोध पक्ष के नेता को इन दिनों प्रति मास पोस्ट खर्च के १००० रुपये मिलते है उसेक बढ़ाकर अब १० हजार रुपये किये जा रहे है।

सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस सत्यनारायण रेड्डी

सूरत और नई दिल्ली में

विजिटिंग कार्ड, बिल बुक, लेटर पैड, बेनर, पोस्टर, आदि का डिजाइन बनवाने के लिए संपर्क करें। (हिन्दी, गुजराती)

महादेव मीडिया

रोहताश यादव 9924144499, 7015339195

हिन्दी, गुजराती न्युज पेपर डिजाइन करवाने के लिए संपर्क करें।

304 केवल कॉम्पलेक्ष नवा गाम, डिंडोली, उधना सूरत।

कांग्रेस के सदस्यों ने साइकल रैली की : सरकार पर आक्षेप

अहमदाबाद। किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने किसान आक्रोश रैली का आयोजन किये जाने के एक दिन बाद आज गुजरात विधानसभा सत्र के दुसरे और अंतिम दिन भी हंगामा किया। कांग्रेस के विधायक साइकल लेकर रैली पर निकले। विधायकों ने एमएलए क्वार्टर्स से लेकर विधानसभा तक साइकल रैली का आयोजन किया। महंगाई और पेट्रोल-डिजल के लगातार बढ़ रहे भाव के खिलाफ यह रैली का आयोजन किया गया। किसानों के प्रश्नों को लेकर कुंभकर्ण की निंद में सोइ हुई भाजप सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस के विधायको ने यह साइकल रैली का आयोजन किया। जिसके चलते सभी लोगों का ध्यान इस और आकर्षित हुआ।



उधना पुलिस स्टेशन ने धारा 363, 376 के आरोपी का किया स्कैच जारी।

दर्शना बेन जरदोश ने सी.सी. टीवी के लिए दिए 10 लाख

सूरत। शहर की सांसद दर्शना बेन जरदोश द्वारा शहर की सुरक्षा के लिए सी.सी.टीवी लगाने हेतु पुलिस कमिश्नर सतीश शर्मा को 10 लाख रुपए का चेक दिया गया। दर्शना बेन ने बताया की शहर मे हों रहे आए दिन अपराधों को रोकने के लिए सूरत शहर की पुलिस

सुरतैदी से अपना काम कर रही है लेकिन नई टेकनोलोजी लाने से पुलिस का काम आसान होगा और पुलिस अपराधियों तक आसानी से पहुंच सकेंगी इस लिए उन्होंने शहर भर में सी.सी.टीवी लगवाने के लिए 10 लाख रुपए का चेक दिया है।